वर्ष 38 अंक 314
पृष्ठ 20+4=24
लखनऊ, मंगलवार
5 सितंबर 2017
नगर संस्करण
मूल्य ₹ 3.00

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

तस्मै श्री गुरवे नमः

अब मात्र ₹ 3.00 में

अच्छा शिक्षक वह है जो जीवनपर्यंत विद्यार्थी बना रहता है। वह केवल किताबों से ही नहीं, अपितु अपने विद्यार्थियों से भी सीखता है।
–डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

www.jagran.com
उत्तर प्रदेश • दिल्ली • मध्य प्रदेश • हरियाणा • उत्तराखण्ड • बिहार • झारखंड • पंजाब • जम्मू-कश्मीर • हिमाचल प्रदेश • पश्चिम बंगाल से प्रकाशित

लेसा के रवैये से सोलर पावर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ता हो रहे निराश

रीडिंग आती नहीं, भेजा 46 हजार का बिल

जागरण संवाददाता, लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 के मिशन में 'सौर-ऊर्जा' से एक लाख मेगावाट विद्युत आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश में भी सौर ऊर्जा से बिजली तैयार करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लोगों को यह सौदा मुनाफे का भी लग रहा है। इसलिए सोलर पावर प्लांट लगाने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। लेकिन लेसा द्वारा बिलिंग की व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं की गई है। इसके चलते सोलर पॉवर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं को अनावश्यक दौड़ लगानी पड़ रही है।

ताजा मामला गोमती नगर का है। राजधानी का पहला सोलर पावर प्लांट लगाने वाले डॉ. भरत राज सिंह को लेसा ने 46 हजार रुपये का बिजली का एक महीने का बिल भेज दिया है। पांच किलो वॉट का सोलर पावर प्लांट लगाने वाले डॉ. सिंह हतप्रभ हैं। लेसा की इस लापरवाही की शिकायत उन्होंने उच्चाधिकारियों से भी की है।

'नेट –मीटरिंग' बिलिंग सिस्टम अथवा कनेक्शन की विंडो तक नहीं है तैयार, लेसा के कर्मचारियों में प्रशिक्षण का भी अभाव

डॉ. सिंह का कहना है कि विगत दो-वर्षों में उ.प्र. विद्युत निगम 'नेट -मीटरिंग' बिलिंग सिस्टम अथवा कनेक्शन की विंडो तक नहीं तैयार कर सका है। उन्होंने बताया कि बीती तीन अगस्त को उनका एक माह का बिजली का बिल लेसा ने 45,899 रुपये भेजा है। इसकी वजह यह है कि रीडिंग लेने वाले प्रशिक्षित ही नहीं है। नेट-मीटर बिल की गणना करने वाले कर्मी ने 1299 यूनिट

के स्थान पर दो-वर्षों के दौरान कुल विद्युत खर्च में से पिछले माह के 'नेट-विद्युत खर्च' को घटाकर 6801 यूनिट का एक माह का बिल भेज दिया। उनका कहना है कि इस बारे में विद्युत निगम के वरिष्ठ अधिकारियों से बात भी की परन्तु अभी तक बिल ठीक नहीं किया गया है। डॉ. सिंह का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए क्योंकि ऐसी लापरवाही से सोलर पावर प्लांट लगाने वाले हलकान हो रहे हैं जिसका सीधा असर प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 के सोलर पावर मिशन पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने पेरिस में दो प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने की संस्तुति की है, जिसकी विश्व भर में सराहना हो रही है। ऐसे में इस प्रकार की लापरवाही लोगों को हतोत्साहित कर सकती है।

उधर अधीक्षण अभियंता सीपी यादव स्वीकारते हैं कि बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जा सका है, जिससे उपभोक्ताओं यह पता नहीं लग पा रहा है कि उन्होंने कितनी बिजली लेसा से ली और कितनी लेसा को दी। हालांकि उपभोक्ताओं की शिकायत पर उनका बिल दुरुस्त करा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां तक नेट मीटर की दिक्कत का प्रश्न है तो उपभोक्ता स्वयं नेट मीटर खरीद कर टेस्टिंग के लिए लेसा को दे सकता है।